



गरवी गुजरात

PRGI No. GUJHIN/2011/39228

# गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 16

अंक : 034

दि. 03.06.2026,

बुधवार

पाना : 04

किंमत : 00.50 पैसा

# क्या बंगाल में दोहराणा महाराष्ट्र का सियासी अध्याय? तृणमूल में बगावत की आहट से ममता की सबसे बड़ी परीक्षा

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति इन दिनों एक ऐसे मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है, जहां राज्य की सबसे प्रभावशाली क्षेत्रीय राजनीतिक ताकतों में से एक तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) अपने गठन के बाद के सबसे बड़े आंतरिक संकट से जूझती नजर आ रही है। हालिया विधानसभा चुनाव में सत्ता गंवाने के बाद पार्टी के भीतर असंतोष, नेतृत्व को लेकर सवाल और विधायकों की नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेजी से फैल रही है कि टीएमसी के भीतर महाराष्ट्र की शिवसेना जैसी टूट की जमीन तैयार हो रही है और यदि हालात नहीं संभले तो पार्टी को अपने विधायकों के साथ-साथ चुनाव चिह्न तक पर चुनौती का सामना करना पड़ सकता है।

पार्टी में उठे इस सियासी तूफान की जड़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति को लेकर पैदा हुआ विवाद माना जा रहा है। यही विवाद धीरे-धीरे इतना बढ़ गया कि उसने टीएमसी नेतृत्व और कई विधायकों के बीच अविश्वास की खाई पैदा कर दी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नेता प्रतिपक्ष बनना जाए, जबकि पार्टी नेतृत्व ने वरिष्ठ नेता शोभनदेव चट्टोपाध्याय के नाम को आगे बढ़ाया। विवाद तब और बढ़ गया जब ऋतब्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने आरोप लगाया कि नेता प्रतिपक्ष के समर्थन संबंधी दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर कथित रूप से बिना अनुमति के दर्शाए गए। इस मामले की शिकायत

दरअसल, विधानसभा में विपक्ष के नेता के चयन को लेकर पार्टी के भीतर दूधे बने गए। एक वर्ग चाहता था कि युवा विधायक ऋतब्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए, जबकि पार्टी नेतृत्व ने वरिष्ठ नेता शोभनदेव चट्टोपाध्याय के नाम को आगे बढ़ाया। विवाद तब और बढ़ गया जब ऋतब्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने आरोप लगाया कि नेता प्रतिपक्ष के समर्थन संबंधी दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर कथित रूप से बिना अनुमति के दर्शाए गए। इस मामले की शिकायत



विधानसभा सचिवालय तक पहुंची और देखते ही देखते यह विवाद टीएमसी की आंतरिक राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। पार्टी नेतृत्व ने इस घटनाक्रम को अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधि मानते हुए ऋतब्रत बनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी से निष्कासित कर दिया। लेकिन यह कार्रवाई विवाद को समाप्त करने के बजाय और अधिक भड़काने वाली साबित हुई। दोनों नेताओं के निष्कासन के बाद कई

अनुपस्थित रहे। पार्टी ने इसके पीछे स्थानीय राजनीतिक परिस्थितियों और व्यस्तताओं को कारण बताया, लेकिन राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने इसे संगठन के भीतर बढ़ती नाराजगी का संकेत माना। इस बीच टीएमसी के निलंबित प्रवक्ता ऋतु दत्ता के दावों ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया। उन्होंने दावा किया कि लगभग 50 विधायक ऋतब्रत बनर्जी के संपर्क में हैं और वे स्वयं को "असली तृणमूल कांग्रेस" बताने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बागी खेमे द्वारा पार्टी के प्रतिष्ठित 'जोड़ा फूल' चुनाव चिह्न पर भी दावा ठोकने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने राज्य की राजनीति में भारी हलचल पैदा कर दी है।

बंगाल की राजनीति में इस घटनाक्रम की तुलना लगातार महाराष्ट्र में हुई शिवसेना की ऐतिहासिक टूट से की जा

रही है। वहां एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बड़ी संख्या में विधायकों ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत की थी, जिसके बाद पार्टी दो हिस्सों में बंट गई थी और अंततः चुनाव चिह्न को लेकर भी कानूनी और राजनीतिक संघर्ष हुआ था। बंगाल में भी अब वही सवाल उठ रहा है कि यदि बड़ी संख्या में विधायक अलग गुट बनाते हैं तो क्या टीएमसी को वैसी ही चुनौती का सामना करना पड़ सकता है।

राजनीतिक समीकरणों की दृष्टि से भी यह मामला बेहद महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में टीएमसी के 80 विधायक हैं। दलबदल विरोधी कानून के तहत किसी भी गुट को वैध विभाजन का दावा करने के लिए कम से कम दो-तिहाई विधायकों का समर्थन चाहिए, जो लगभग 53 विधायकों के बराबर है। ऐसे में 50 विधायकों के समर्थन का दावा इस आंकड़े के बेहद करीब माना जा रहा है और इसी कारण यह मामला केवल अटकलों तक सीमित नहीं रह

गया है। दूसरी ओर ममता बनर्जी और उनके करीबी नेता लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी एकजुट है और कुछ लोग सुनियोजित तरीके से भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया है कि उनकी पार्टी को तोड़ने के लिए दबाव और प्रलोभन का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं वरिष्ठ नेता कुणाल घोष ने विधायकों से भावनात्मक अपील करते हुए कहा है कि वे ममता बनर्जी के नेतृत्व और पार्टी के संघर्ष को याद रखें।

फिलहाल ऋतब्रत बनर्जी ने नई पार्टी बनाने की संभावना से इनकार किया है, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा है कि तृणमूल कांग्रेस में अब स्वतंत्र रूप से अपनी बात रखने की गुंजाइश कम होती जा रही है। उनके इस बयान ने भी यह संकेत दिया है कि असंतोष केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि संगठनात्मक स्तर पर मौजूद है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि

आगामी बजट सत्र और आने वाले कुछ सप्ताह टीएमसी के भविष्य के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। यदि नेतृत्व असंतुष्ट विधायकों को साथ लाने में सफल रहता है तो पार्टी इस संकट से उबर सकती है, लेकिन यदि मतभेद और बढ़ते हैं तो बंगाल की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। 1998 में गठन के बाद पहली बार तृणमूल कांग्रेस ऐसी स्थिति में पहुंची है, जहां उसके संगठनात्मक अस्तित्व और नेतृत्व क्षमता दोनों की एक साथ परीक्षा हो रही है।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह असंतोष कुछ दिनों में शांत हो जाएगा या फिर यह वास्तव में महाराष्ट्र जैसी राजनीतिक पुनर्संरचना का रूप ले लेगा। इसका जवाब आने वाले दिनों की घटनाएं ही देंगी, लेकिन इतना तय है कि तृणमूल कांग्रेस के सामने यह अब तक की सबसे कठिन राजनीतिक चुनौती बन चुकी है।

## रुद्रम-2 ने बढ़ाई भारत की मारक क्षमता: दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम पर करेगा सटीक प्रहार

नई दिल्ली। भारत ने स्वदेशी रक्षा तकनीक के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए अपनी सामरिक शक्ति को नई मजबूती प्रदान की है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा विकसित उन्नत एंटी-रेडिएशन मिसाइल 'रुद्रम-2' का भारतीय वायुसेना के Su-30MKI लड़ाकू विमान से सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण ने न केवल मिसाइल की तकनीकी क्षमता को प्रमाणित किया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि भारत अब आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और हवाई अभियानों में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।



रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार रुद्रम-2 एक अत्याधुनिक एयर-टू-सेरफेस एंटी-रेडिएशन मिसाइल है, जिसे विशेष रूप से दुश्मन के रडार, एयर डिफेंस सिस्टम, संचार केंद्रों और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तंत्र को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी अनुमानित मारक क्षमता लगभग 300 किलोमीटर तक है, जो इसे भारतीय वायुसेना के लिए एक अत्यंत प्रभावशाली हथियार बनाती है। इसकी लंबी दूरी से लक्ष्य को भेदने की क्षमता के कारण लड़ाकू विमानों को दुश्मन की हवाई सीमा के अत्यधिक निकट जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिससे उनकी सुरक्षा भी बढ़ जाती है।

रुद्रम-2 की सबसे बड़ी विशेषता इसकी उन्नत लक्ष्य-भेदी क्षमता है। सामान्यतः जब किसी देश के रडार सिस्टम को यह पता चलता है कि

तक दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस नेटवर्क सक्रिय रहते हैं, तब तक लड़ाकू विमानों के लिए गहरे अंदर तक प्रवेश करना जोखिम भरा होता है। रुद्रम-2 ऐसे रडार स्टेशनों को खोजकर नष्ट करती है और आगे आने वाले विमानों के लिए सुरक्षित मार्ग तैयार करती है। युद्धक रणनीति में इस प्रकार के अभियानों को SEAD अर्थात् 'सप्रेशन ऑफ एनियो एर डिफेंस' कहा जाता है। दुनिया की प्रमुख वायु सेनाएं लंबे समय से इस रणनीति का उपयोग करती रही हैं। अब रुद्रम-2 के माध्यम से भारतीय वायुसेना भी इस क्षेत्र में अपनी क्षमता को और अधिक मजबूत कर रही है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 'फेस मल्टीप्लायर' रुद्रम-2 को दुश्मन के लिए 'फेस मल्टीप्लायर' सख्त हो सकती है। किसी भी युद्ध में सबसे पहले दुश्मन की हवाई सुरक्षा प्रणाली को कमजोर करना आवश्यक माना जाता है। जब

## मरीजों के हक पर डाका नहीं चलेगा: अवैध वसूली पर सिविल अस्पताल का बड़ा एक्शन

सूत। सूत के नए सिविल अस्पताल में मरीजों से कथित अवैध वसूली का मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन ने त्वरित और सख्त कार्रवाई करते हुए संबंधित कंप्यूटर ऑपरेटर को तत्काल ड्यूटी से हटा दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में केस विंडो पर कार्यरत आउटसोर्सिंग एजेंसी का कर्मचारी मरीजों से 20 रुपये लेते हुए दिखाई देने का दावा किया गया था। वीडियो सामने आते ही अस्पताल प्रशासन हरकत में आया और मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के साथ-साथ जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। देश के सबसे व्यस्त सरकारी अस्पतालों में गिने जाने वाले सूत के नए सिविल अस्पताल में प्रतिदिन हजारों मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। इनमें बड़ी संख्या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की होती है, जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में मरीजों से कथित रूप से अतिरिक्त राशि वसूलने की घटना ने अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिया है कि मरीजों के हितों के साथ किसी भी प्रकार का



समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। मामले के सामने आते ही मेडिकल सुपरिटेण्डेंट डॉ. पारुल वडगामा की अध्यक्षता में आपात समीक्षा बैठक बुलाई गई। बैठक में रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर (आरएमओ) डॉ. केतन नायक, प्रभारी नर्सिंग सुपरिटेण्डेंट इकबाल कड़ीवाल, विभिन्न आउटसोर्सिंग एजेंसियों के प्रतिनिधि, सुपरवाइजर, डेटा ऑपरेटर और सुरक्षा अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में अस्पताल की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए स्पष्ट किया गया कि भ्रष्टाचार, रिस्कव्योरी, वित्तीय अनियमितताओं और अनुशासनहीनता के प्रति अस्पताल की नीति पूरी तरह जीरो टॉलरेंस की होगी। डॉ. पारुल वडगामा ने सभी कर्मचारियों को निर्देश दिए कि अस्पताल आने वाले प्रत्येक

मरीज के साथ सम्मानजनक, संवेदनशील और मानवीय व्यवहार किया जाए। उन्होंने कहा कि गरीब और जरूरतमंद मरीज अस्पताल की सेवाओं पर भरोसा करके यहां आते हैं, इसलिए उनकी सुविधा और सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान मरीजों का नाम, पता और अन्य विवरण पूरी साफधानी के साथ दर्ज किए जाएं ताकि इलाज की प्रक्रिया में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हो सके। साथ ही कर्मचारियों की समयबद्ध उपस्थिति और कार्य निष्पत्ति को भी लगातार निगरानी करने को कहा गया है।

अस्पताल प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में यदि किसी भी कर्मचारी के खिलाफ रिश्तत दर्ज किए जाएं, ताकि इलाज की प्रक्रिया में केस विंडो पर कार्यरत आउटसोर्सिंग एजेंसी का कर्मचारी मरीजों से 20 रुपये लेते हुए दिखाई देने का दावा किया गया था। वीडियो सामने आते ही अस्पताल प्रशासन हरकत में आया और मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के साथ-साथ जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। देश के सबसे व्यस्त सरकारी अस्पतालों में गिने जाने वाले सूत के नए सिविल अस्पताल में प्रतिदिन हजारों मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। इनमें बड़ी संख्या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की होती है, जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में मरीजों से कथित रूप से अतिरिक्त राशि वसूलने की घटना ने अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिया है कि मरीजों के हितों के साथ किसी भी प्रकार का

## तमिलनाडु भाजपा में भूचाल: अन्नामलाई ने नितिन नवीन को सौंपा इस्तीफा नई राजनीतिक पारी की तैयारी से दक्षिण की राजनीति में हलचल

नई दिल्ली/चेन्नई। तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है, जिसने न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि पूरे दक्षिण भारतीय राजनीतिक परिदृश्य को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। तमिलनाडु भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के सबसे लोकप्रिय चेहरों में शामिल रहे के अन्नामलाई ने भाजपा से अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने नई दिल्ली पहुंचकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की और उन्हें पांच पन्नों का इस्तीफा सौंपा। इसके बाद उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और संगठन के वरिष्ठ नेताओं से भी चर्चा की। इस घटनाक्रम को भाजपा की दक्षिण भारत रणनीति के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

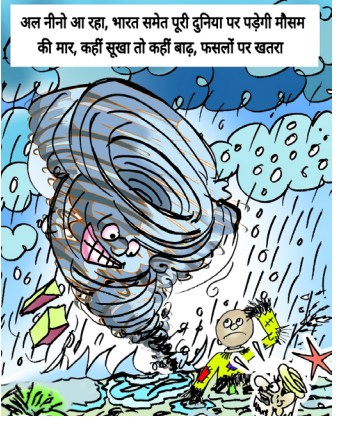


भाजपा के लिए केवल एक संगठनात्मक नुकसान नहीं बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अन्नामलाई के इस्तीफे को लेकर कई महीनों से अटकलें लगाई जा रही थीं। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष पद से हटाए जाने और नैनार नागेंद्र को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से ही उनके भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे थे। इसके अलावा राज्य में भाजपा और एआईएडीएमके के बीच बढ़ती राजनीतिक नजदीकियों को लेकर भी अन्नामलाई की असहमति की खबरें लगातार सामने आती रही थीं। बताया जाता है कि वह तमिलनाडु में भाजपा को स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित करने के पक्षधर थे, जबकि पार्टी को केंद्रीय नेतृत्व गठबंधन की राजनीति को प्राथमिकता दे रहा था।

राजनीतिक सूरजों के अनुसार अन्नामलाई दिल्ली पहुंचने से पहले ही अपना अंतिम निर्णय ले चुके थे। उनकी मुलाकातें किसी समझौते या मनाफे की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं थीं, बल्कि वह पार्टी नेतृत्व को सम्मानपूर्वक अपने फैसले से अवगत कराने के लिए दिल्ली गए थे। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने इस्तीफे में संगठनात्मक और वैचारिक दोनों प्रकार के कारणों का उल्लेख किया है। सबसे अधिक चर्चा उनकी संभावित नई राजनीतिक पारी को लेकर हो रही है। अन्नामलाई के समर्थकों ने सोशल

किया था। वर्ष 2020 में भाजपा में शामिल होने के बाद उन्होंने तेजी से अपनी पहचान बनाई और कुछ ही वर्षों में तमिलनाडु भाजपा के सबसे प्रभावशाली नेता बन गए। उनकी 'एन मन, एन मक्कल' यात्रा ने उन्हें राज्य के दूरदराज इलाकों तक पहुंचाया और भाजपा को ग्रामीण क्षेत्रों में भी चर्चा का विषय बनाया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि अन्नामलाई वास्तव में नई पार्टी का गठन करते हैं तो इसका असर केवल भाजपा पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि द्रमुक (DMK), एआईएडीएमके और अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके के राजनीतिक समीकरणों पर भी पड़ सकता है। विशेष रूप से युवा मतदाताओं और शहरी मध्यम वर्ग के बीच उनकी लोकप्रियता उन्हें एक अलग पहचान दे सकती है। हालांकि किसी नई पार्टी को मजबूत संगठन खड़ा करने और चुनावी सफलता हासिल करने में लंबा समय लग सकता है।

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार प्राप्त करने के लिए आज ही गरवी गुजरात हिंदी चैनल देखिये





# 'लोकल से ग्लोबल' की सशक्त उड़ान : गुजरात सरकार की हस्तकला सेतु योजना बनी परंपरागत कला-कारीगरी के लिए मजबूत प्रोत्साहन का सेतु

► हस्तकला सेतु योजना अंतर्गत 102.08 करोड़ रुपए की बिक्री, 50,000 से अधिक रोजगार का सृजन  
► योजनांतर्गत 21,690 से अधिक कारीगरों का पंजीकरण, जिनमें 82 प्रतिशत महिलाएँ  
► प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन को भली-भाँति आगे बढ़ा रहे मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

गांधीनगर, 02 जून : गुजरात की समृद्ध हस्तकला परंपरा की सदियों से देश-विदेश में अपनी विशिष्ट पहचान है। बदलते आर्थिक परिप्रेक्ष्य तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धा के समय में इन कारीगरों को सशक्त बनाना समय की बड़ी आवश्यकता बनी है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भी 'विकास भी, विरासत भी', 'आत्मनिर्भर भारत', 'लोकल फॉर लोकल' जैसे मंत्रों द्वारा परंपरागत कला विरासत को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देने का विजन दिया है और गुजरात में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल इस विजन को भली-भाँति आगे बढ़ा रहे हैं।

## मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री योगेशभाई पटेल के निधन पर गहरा शोक और दुःख व्यक्त किया

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री योगेशभाई पटेल के निधन पर गहरा शोक और दुःख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत योगेशभाई को स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने जनप्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रसेवा और जनसेवा के कार्यों में निरंतर कर्तव्यनिष्ठ रहकर आम जनता के हृदय में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त किया था। उन्होंने परम कृपालु परमात्मा से प्रार्थना की कि दिवंगत योगेशभाई की आत्मा को शांति प्रदान करें तथा शोकसंतप्त परिवार और उनके समर्थकों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति दें।

## चलती ट्रेन में गूजी किलकारी! जबलपुर-सोमनाथ एक्सप्रेस में महिला ने बच्चे को दिया जन्म, मां एवं नवजात दोनों सुरक्षित

भारतीय रेल की यात्री सेवा एवं मानवीय संवेदनशीलता का एक प्रेरणादायक उदाहरण उस समय देखने को मिला, जब गाड़ी संख्या 11466 जबलपुर-सोमनाथ एक्सप्रेस में यात्रा कर रही एक गर्भवती महिला ने चलती ट्रेन में ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। रेलवे कर्मचारियों की तत्परता, सहयात्रियों के सहयोग तथा विभिन्न विभागों के उत्कृष्ट समन्वय से प्रसव सुरक्षित रूप से संपन्न हुआ। वर्तमान में मां एवं नवजात दोनों स्वस्थ हैं तथा विरमगाम के अस्पताल में उनका उपचार एवं चिकित्सकीय देखभाल जारी है।



महिला ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे प्रशासन ने आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की। विरमगाम स्टेशन पर पूर्व समन्वय के तहत चिकित्सा सहायता एवं एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई। महिला के पति से अवगत कराया तथा तत्परता से रेलवे बेडशेड उपलब्ध कराया। इस बीच चांदलोडिया स्टेशन पर होने के बाद प्रसव पीड़ा बढ़ने पर कोच में उपस्थित महिला सहयात्रियों ने अत्यंत संवेदनशीलता एवं साहस का परिचय देते हुए गर्भवती महिला की सहायता की। उनके सहयोग से चलती ट्रेन में ही सुरक्षित प्रसव कराया गया और

टीटीई श्री रामजीवन कुमार ने मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए महिला एवं उसके परिजनों के लिए आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई तथा चाय-पानी की व्यवस्था भी करवाई। उनकी तत्परता एवं कर्तव्यनिष्ठा की यात्रियों द्वारा सराहना की गई।

मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने इस सराहनीय कार्य के लिए संबंधित कर्मचारियों, विशेष रूप से ऑन ड्यूटी टीटीई श्री रामजीवन कुमार तथा सहयोग करने वाली महिला यात्रियों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि रेलवे केवल यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का माध्यम नहीं, बल्कि आवश्यकता के समय उनके साथ खड़े रहने वाली एक संवेदनशील संस्था भी है। उन्होंने कर्मचारियों को भविष्य में भी इसी प्रकार यात्रियों की सहायता एवं सेवा के लिए सदैव तत्पर रहने हेतु प्रोत्साहित किया। यात्री परिवार ने रेलवे प्रशासन, ऑन ड्यूटी स्टाफ एवं सहयोग करने वाले सहयात्रियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनकी तत्पर सहायता और मानवीय व्यवहार की सराहना की।

## कोठगांगड़ गांव के निकट रेलवे द्वारा रिकॉर्ड समय में निर्मित जल निकासी संरचना से ग्रामीणों को मिलेगी बड़ी राहत

जन समस्याओं के निवारण करने की अपनी सतत प्रतिबद्धता के तहत पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा के दिशा निर्देशों के अनुरूप साबरमती-बोटाद रेलखंड पर कोठगांगड़ गांव के निकट किलोमीटर 76/6-7 पर 2 मीटर x 2 मीटर आकार के आरसीसी बॉक्स ब्रिज (जल मार्ग) का निर्माण एवं स्थापना कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किया है। यह महत्वपूर्ण कार्य मात्र दो माह के रिकॉर्ड समय में पूर्ण किया गया।



दिनांक 01 जून 2026 को 200 टन क्षमता वाले क्रेन की सहायता से बॉक्स ब्रिज का सुरक्षित एवं सटीक रूप से सफलतापूर्वक ईंशर्शन (Insertion) किया गया। इस परियोजना के पूर्ण होने से क्षेत्र की जल



के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है। इस योजना का क्रियान्वयन कुटीर एवं ग्रामोद्योग आयुक्त के अधीनस्थ इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन-कॉन्ट्रोल (इंटेक्सट-सी) द्वारा किया जा रहा है, जबकि भारतीय

उद्यमिता विकास संस्थान (ईडीआईआई) ने इस योजना में नॉलेज पार्टनर के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शुरुआत में यह योजना 2019-20 से तीन वर्ष के लिए प्रस्तावित थी, परंतु कोविड-19

महामारी के चलते इसे 2025-26 तक विस्तृत किया गया। इस योजना पर राज्य सरकार द्वारा लगभग 58 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता इसका विशाल दायरा है। यह योजना गुजरात के सभी 34 जिलों में लागू की गई है। योजनांतर्गत अब तक 21,690 से अधिक कारीगरों का पंजीकरण किया गया है, जिनमें 82 प्रतिशत महिलाएँ हैं। सामाजिक समावेशिता की दृष्टि से भी यह योजना महत्वपूर्ण है, कारण कि लाभार्थियों में 21 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 20 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति तथा 34 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के कारीगर शामिल हैं।

15 हजार से अधिक कारीगरों को उद्यमिता प्रशिक्षण, 70 से अधिक मास्टर ट्रेनर्स तथा 150 से अधिक मॉडर्न का नेटवर्क

हस्तकला सेतु योजनांतर्गत कारीगरों को केवल आर्थिक सहायता ही नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यापक

प्रशिक्षण भी दिया गया है। 15,586 कारीगरों को उद्यमिता विकास प्रशिक्षण दिया गया है, जबकि 9,292 कारीगरों को उनके क्षेत्र से जुड़ा विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण मिला है। इसके अतिरिक्त, 70 से अधिक मास्टर ट्रेनर्स तथा 150 से अधिक मॉडर्न का नेटवर्क तैयार किया गया है, जो कारीगरों को निरंतर मार्गदर्शन दे रहा है।

9,300 कारीगरों को बीटूबी ऑर्डर द्वारा सीधे बाजार से जोड़ा गया, 102.08 करोड़ रुपए की कुल बिक्री दर्ज हुई

बाजार के साथ कनेक्टिविटी इस योजना का सबसे मजबूत पहलू है। लगभग 9,300 कारीगरों को बीटूबी ऑर्डर द्वारा सीधे बाजार से जोड़ा गया है। इसके अलावा, 7 बीटूबी मॉड तथा 4 फैशन शो द्वारा कारीगरों एवं डिजाइनरों के बीच सुदृढ़ संबंध स्थापित हुआ है। डिजिटल युग के अनुरूप, 2,000 से अधिक कारीगरों को डिजिटल मार्केटिंग का प्रशिक्षण देकर उन्हें अमेजन, फ्लिपकार्ट समर्थ, मीशो

तथा इटसी जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जोड़ा गया है।

इस योजना का आर्थिक प्रभाव भी बहुत प्रभावशाली रहा है। योजनांतर्गत अब तक 102.08 करोड़ रुपए की कुल बिक्री दर्ज हुई है और 50,000 से अधिक नए रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। साथ ही, मौजूदा 5,900 से अधिक कारीगरों को अतिरिक्त सहायता एवं मार्गदर्शन मिला है।

योजनांतर्गत आय अर्जित करने वाले कला-कारीगरों की संख्या 9 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत तक पहुंची यदि कारीगरों की आय की बात करें, तो हस्तकला सेवा सेतु योजना से पहले केवल 9 प्रतिशत कारीगर ही 15,000 रुपए से अधिक मासिक आय अर्जित कर पाते थे, जबकि आज यह आंकड़ा 50 प्रतिशत तक बढ़ गया है। हस्तकला को आय के मुख्य स्रोत के रूप में अपनाने वाले कारीगरों की संख्या भी 20 प्रतिशत से बढ़कर 45 प्रतिशत हो गई है। इसके अलावा, 73 प्रतिशत कारीगर अब

प्रदर्शियों तथा मेलों द्वारा सीधे बाजार तक पहुंच बना रहे हैं।

यद्यपि योजना के सफल क्रियान्वयन के दौरान कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। इनमें दस्तावेजों का अभाव, वित्तीय समन्वय में विलंब, आधुनिक टेक्नोलॉजी अपनाने में संकोच तथा प्रभावी मार्केटिंग तंत्र का अभाव प्रमुख हैं, परंतु गुजरात सरकार ने इन चुनौतियों को दूर करने के लिए टेक्नोलॉजी अपडेशन, डिजाइन नवीनता, बाजार विविधता तथा सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्राथमिकता दी। हस्तकला सेतु योजना केवल एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि कारीगरों के जीवन में परिवर्तन लाने वाली एक क्रांतिकारी पहल बनी है। इस योजना ने केवल रोजगार सृजन ही नहीं किया, बल्कि गुजरात की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाई है। 'लोकल टू ग्लोबल' की आगे यह कदम भारत को आत्मनिर्भर बनाने के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

## पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल का शानदार प्रदर्शन: मई 2026 में 688 करोड़ का रिकॉर्ड राजस्व, यात्री और मालभाड़ा आय में भारी उछाल

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल ने मई 2026 के दौरान विभिन्न वाणिज्यिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राजस्व अर्जन, माल परिवहन, यात्री सुविधाओं के विस्तार तथा गैर-किराया आय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ अर्जित की हैं। मंडल ने इस महीने लगभग 688 करोड़ का सकल राजस्व (Gross Revenue) अर्जित किया है, जो पिछले वर्ष मई 2025 की तुलना में 7.01% अधिक है।

राजस्व के मुख्य आंकड़े:

- यात्री राजस्व (Passenger Revenue): 22.68% की भारी बढ़ोतरी के साथ 144.95 करोड़ दर्ज किया गया, जो पिछले साल मई में 118.15 करोड़ था।
- अन्य कोचिंग राजस्व (Other Coaching Revenue): पिछले वर्ष के 16.47 करोड़ से 52.40% बढ़कर 25.10 करोड़ तक पहुंच गया।
- मालभाड़ा राजस्व (Goods Revenue): मई 2026 में 517.34



करोड़ रहा, जिसमें पिछले साल (507.72 करोड़) की तुलना में लगभग 2% की

वृद्धि देखी गई।

► यात्रियों की संख्या: प्रारंभिक

यात्रियों की संख्या (No. of Orig. Passengers) 12.67% बढ़कर 34.15 लाख हो गई।

मालभाड़े (Freight) में ऐतिहासिक रिकॉर्ड:

- अहमदाबाद मंडल के कई प्रमुख टर्मिनलों और साइडिंग्स ने अब तक का अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ मासिक मालभाड़ा राजस्व दर्ज किया है:
- देशलपर (DSLPL) फ्रेट टर्मिनल: 13.40 करोड़ का अब तक का सर्वश्रेष्ठ राजस्व हासिल किया।
- इफको (IFPCO) साइडिंग खोडियार: 9.98 करोड़ का रिकॉर्ड राजस्व दर्ज किया।
- सानोसरा (SNSR) फ्रेट टर्मिनल: 10.75 करोड़ का अपना सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया।
- बेंटोनाइट लोडिंग (Bentonite Loading): बेंटोनाइट की लोडिंग में मंडल को 24.29 करोड़ का ऐतिहासिक मासिक राजस्व प्राप्त हुआ।
- बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट (BDU)

के विशेष प्रयास:

मंडल की बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट (BDU) ने नए ग्राहकों, गंतव्यों और नई सामग्रियों को जोड़कर राजस्व बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

- नई सामग्री: आईटीसी लिमिटेड द्वारा कांडला पोर्ट से पोल्लाची जंक्शन तक 'सोयाबीन एक्सप्रेस' और 'फ्लेक्स' की पहली मिनी रैक लोड की गई, जिससे 42.06 लाख का अतिरिक्त राजस्व मिला।
- नए ग्राहक: मेसर्स मैग्नेस माईंस एंड मिनरल्स लिमिटेड ने सानोसरा से भूषण खोडियार पर एंड स्टील लिमिटेड की निजी साइडिंग तक बेंटोनाइट की रैक भेजकर 1.07 करोड़ का राजस्व उत्पन्न किया।
- औद्योगिक नमक, बेंटोनाइट और जैविक खाद जैसी सामग्रियों को देश के विभिन्न डिवीजनों (जैसे वडोदरा, भावनगर, सिक्ंदरगढ़, कोटा, पुणे, जम्मू और खुर्दा रोड) के नए गंतव्यों तक सफलतापूर्वक भेजा गया।
- नॉन-फेयर रेवेन्यू (NFR) और

पार्सल में नवाचार:

- गेम जोन अनुबंध: महेशाणा (MSH) स्टेशन पर 454 वर्ग मीटर क्षेत्र में पांच वर्षों के लिए 'गेम जोन' के विकास और संचालन का ई-ऑक्शन कॉन्ट्रैक्ट सफलतापूर्वक आवंटित किया गया, जिससे 44.25 लाख का राजस्व मिला।
- पार्सल ई-ऑक्शन: मई महीने में आयोजित ई-ऑक्शन के माध्यम से 11 पार्सल संपत्तियों को तीन साल के लिए लीज पर दिया गया, जिससे 20.08 करोड़ का कुल राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है।
- मसालों की पार्सल रैक: महेशाणा से अन्ना और ऊंझा से मिर्जा के लिए मसालों की पहली पार्सल रैक चलाई गई, जिससे क्रमशः 24.79 लाख और 27.15 लाख का राजस्व मिला।
- यात्री सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
- ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त मांग को पूरा करने हेतु 33 विशेष ट्रेन यात्राओं का संचालन किया गया तथा 43 अतिरिक्त कोच लगाए गए।

► इन प्रयासों से लगभग 0.55 लाख यात्रियों को सुविधा प्रदान की गई तथा 6.79 करोड़ का अतिरिक्त यात्री राजस्व अर्जित हुआ।

पुन-दिल्ली एक्सप्रेस का शुभारंभ: 22 मई 2026 को माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्रभाई पटेल ने वीटिंग कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जालौर-पाली मारवाड़ के रास्ते पहली बार 'भुज से बुज-दिल्ली एक्सप्रेस' को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिससे कच्छ और देश की राजधानी के बीच कनेक्टिविटी मजबूत हुई है। टिकट चेंजिंग और स्वच्छता अभियान: बिना टिकट और अनियमित यात्रा पर अंकुश लगाने के लिए विभिन्न स्टेशनों पर विशेष (Fortress) जॉच अभियान चलाए गए, जिससे मई महीने में लगभग 3.00 करोड़ की टिकट चेंजिंग आय होने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, स्टेशनों पर गंदगी फैलाने और धुकने वाली के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एंटी-लिटरिंग यामलों के तहत 1.38 लाख का जुर्माना वसूल किया गया।

## प्रतापनगर रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कायाकल्प

वडोदरा का प्रतापनगर स्टेशन अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह वर्ष 1880 में नैरो गेज रेलवे के आगमन का प्रमुख केंद्र रहा है। वर्ष 1922 में यहां प्रतापनगर में एक महत्वपूर्ण रेलवे वर्कशॉप की स्थापना की गई थी। वर्तमान में इस स्टेशन को एक रणनीतिक सैटेलाइट स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे वडोदरा स्टेशन पर यातायात का दबाव कम किया जा सके। यहां लंबी दूरी की ट्रेनों के संचालन तथा आधुनिक यात्री सुविधाओं की योजना है, जिससे क्षेत्रीय संपर्क और यात्रियों की सुविधा में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त, यह स्टैच्यू ऑफ महत्वपूर्ण बौडिंग स्टेशन भी है।

वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके के अनुसार प्रतापनगर रेलवे स्टेशन का यह व्यापक पुनर्विकास न केवल यात्रियों को बेहतर सुविधाएँ प्रदान करेगा, बल्कि वडोदरा शहर की रेलवे अवसंरचना को भी नई ऊँचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

यात्री सुविधाओं का विस्तार :

अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 71.58 करोड़ रुपये की लागत से प्रतापनगर रेलवे स्टेशन का व्यापक पुनर्विकास का कार्य किया गया है जिससे इस स्टेशन को एक नया भव्य स्वरूप मिला है। पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत पुराने 1, 2 एवं 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर यात्री सुविधाओं का विस्तार किया गया है। साथ ही एक नए प्लेटफॉर्म नंबर 4 का विकास किया गया है, जिसमें उच्च स्तरीय प्लेटफॉर्मों का विस्तार एवं पुनर्संरचना किया गया है। प्लेटफॉर्मों



पर आधुनिक प्लेटफॉर्म शोल्डर तैयार किये गए हैं जिससे यात्रियों को बैठने की सुगम व्यवस्था उपलब्ध हो। नए स्टेशन भवन में नए विभिन्न कार्यालयों की स्थापना की गयी है। यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त शौचालयों का निर्माण किया गया है। साथ ही आधुनिक साइनेज व्यवस्था तथा दिव्यांगजन-अनुकूल बुकिंग काउंटर सुविधाओं का विकास किया गया है। इसके अतिरिक्त, स्टेशन पर दो नई लिफ्टों की स्थापना भी की गई है।

आकर्षक द्वितीय प्रवेश द्वार :

प्रतापनगर स्टेशन के द्वितीय प्रवेश द्वार की तरफ नए स्टेशन भवन का निर्माण तथा

वाणिज्यिक क्षेत्र के विकास का कार्य भी किया गया है, जिससे स्टेशन भवन का स्वरूप बेहद आकर्षक हुआ है।

एंट्री क्षेत्र में सुव्यवस्थित यातायात प्रबंधन, पर्याप्त पार्किंग सुविधा, स्पष्ट प्रवेश एवं निकास मार्ग तथा आधुनिक शहरी अवसंरचना विकसित की गई है।

कॉन्कोर्स क्षेत्र का आधुनिकीकरण : यात्रियों को बेहतर अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से स्टेशन के कॉन्कोर्स क्षेत्र का भी आधुनिकीकरण किया गया है। आधुनिक प्लॉरिंग के साथ आकर्षक वॉल क्लोडिंग की गयी है, जिसमें रेलवे के इतिहास की शलक को उकेरा गया है। स्टेशन पर उन्नत प्रकाश व्यवस्था के साथ स्टेशन



परिसर में कलात्मक भित्ति चित्र (म्यूरल्स) स्थापित किए गए हैं, जो स्टेशन को एक नया और आकर्षक स्वरूप प्रदान करते हैं।

दिव्यांगजन-अनुकूल सुविधाएं : दिव्यांगजन यात्रियों के लिए प्लेटफॉर्म को सुगम, सुरक्षित एवं सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने हेतु सभी आवश्यक सुलभ सुविधाएँ उपलब्ध कराई गईं

अनुकूल बुकिंग काउंटर सुविधाओं का विकास किया गया है। फुट ओवर ब्रिज को लिफ्टों से भी जोड़ा गया है जिससे यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर जाने में सुगमता हासिल हो, जिससे यह स्टेशन पूर्णतः दिव्यांगजन-अनुकूल बन सके। यह परियोजना भारतीय रेल के 'यात्री सुविधा, सुगम यात्रा और आधुनिक स्टेशन' के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मीटर चौड़ा फुट ओवर ब्रिज :

स्टेशन के दोनों ओर के शहर तथा प्लेटफॉर्मों को जोड़ने के लिए 12 मीटर चौड़ा फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया गया है। यात्रियों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने हेतु दोनों सिरों पर रैंप की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही फुट ओवर ब्रिज को लिफ्टों से भी जोड़ा गया है। दिव्यांगजन-अनुकूल बुकिंग काउंटर सुविधाओं का विकास किया गया है। फुट ओवर ब्रिज को लिफ्टों से भी जोड़ा गया है जिससे यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर जाने में सुगमता हासिल हो, जिससे यह स्टेशन पूर्णतः दिव्यांगजन-अनुकूल बन सके। यह परियोजना भारतीय रेल के 'यात्री सुविधा, सुगम यात्रा और आधुनिक स्टेशन' के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

## 03 जून को वडोदरा मंडल के वासद-रनोली स्टेशनों के बीच ब्लॉक के कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेंगी

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल पर वासद-रनोली स्टेशनों के बीच ब्रिज नं. 624 (अप लाइन) पर री-गैरिंग कार्य हेतु 03 जून (बुधवार) को 11.15 बजे से 16.45 बजे तक 05.30 घंटे का मेगा ब्लॉक लिया जाएगा। जिसके कारण वडोदरा मंडल से चलने/गुजरने वाली कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। जो इस प्रकार हैं:

पूर्णातः निरस्त ट्रेन

03 जून 2026 की ट्रेन संख्या 19036 मणिनगर-वडोदरा इंटरसिटी एक्सप्रेस पूर्णातः निरस्त रहेंगी।

03 जून 2026 की ट्रेन संख्या 19035 वडोदरा-मणिनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस पूर्णातः निरस्त रहेंगी।



03 जून 2026 की ट्रेन संख्या 12930 वडोदरा- वलसाड इंटरसिटी एक्सप्रेस पूर्णातः निरस्त रहेंगी।

आंशिक निरस्त ट्रेन

03 जून 2026 की ट्रेन संख्या 22960 जामनगर-वडोदरा इंटरसिटी एक्सप्रेस अहमदाबाद स्टेशन पर शांट टर्मिनट

होगी तथा अहमदाबाद-वडोदरा के बीच आंशिक निरस्त रहेंगी।

रिश्ड्यूल होने वाली ट्रेन

1. 03 जून 2026 की ट्रेन संख्या 12010 अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल शताब्दी एक्सप्रेस 40 मिनट रिश्ड्यूल रहेंगी।  
रेगुलट होने वाली ट्रेनें

1. 03 जून 2026 की ट्रेन संख्या 16533 भात की कोठी-केएसआर बैंगलूर एक्सप्रेस 55 मिनट रेगुलेट रहेंगी।

2. 03 जून 2026 की ट्रेन संख्या 12477 जामनगर-श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस 50 मिनट रेगुलेट रहेंगी।

3. 03 जून 2026 की ट्रेन संख्या 20626 भात की कोठी-एमजीआर चेन्नई सेंट्रल एक्सप्रेस 55 मिनट रेगुलेट रहेंगी।

यात्रियों से निवेदन है कि उपरोक्त बदलाव को ध्यान में रखकर यात्रा करें। ट्रेनों के परिवर्तन समय, उधार और संरचना से सम्बंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री [www.enquiry.indianrail.gov.in](http://www.enquiry.indianrail.gov.in) पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

## गुजरात पुलिस की नूतन पहल

# पुलिस भवन में शुरु हुआ 'जनसंपर्क कार्यालय' नागरिकों के लिए बना विश्वास का नया पता

► गुजरात पुलिस की 'सुरक्षा, सेवा और विश्वास' की भावना को उजागर करने वाला सशक्त माध्यम बना जनसंपर्क कार्यालय : राज्य के पुलिस महानिदेशक डॉ. के. एल. एन. राव

► नागरिकों की समस्याओं का सिंगल-विंडो जैसी पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से समय पर समाधान

► राज्य के पुलिस महानिदेशक ने केंद्र का दौरा कर कामकाज की समीक्षा की

गांधीनगर : राज्य के नागरिकों और पुलिस तंत्र के बीच विश्वास तथा पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से पुलिस भवन में 'जनसंपर्क कार्यालय' शुरू किया गया है। राज्य के पुलिस महानिदेशक डॉ. के. एल. एन. राव के मार्गदर्शन में संचालित इस कार्यालय के माध्यम से नागरिकों की शिकायतों, आवेदनों और समस्याओं का उचित एवं न्यायसंगत समाधान समय पर किया जा रहा है। मंगलवार को राज्य के पुलिस महानिदेशक ने इस केंद्र का दौरा कर इसके कामकाज की समीक्षा

की। पुलिस विभाग द्वारा शुरू की गई यह व्यवस्था आज नागरिकों के लिए न्याय प्राप्त करने का सुव्यवस्थित और सशक्त माध्यम बन चुका है। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक आवेदक की बात को सम्मानपूर्वक सुनना, जिला एवं शहर स्तर की पुलिस कार्यालयों के साथ समन्वय स्थापित कर समयबद्ध और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करना है। इस व्यवस्था से आवेदनों पर कार्रवाई में होने वाली देरी समाप्त हुई है और पुलिस के प्रति जनता का



विश्वास और अधिक मजबूत हुआ है। राज्य के पुलिस महानिदेशक डॉ. के. एल. एन. राव ने कहा कि जनसंपर्क

कार्यालय केवल नागरिकों के आवेदन स्वीकार करने का केंद्र नहीं है, बल्कि यह गुजरात पुलिस की 'सुरक्षा, सेवा

और विश्वास' की भावना को साकार करने का एक सशक्त माध्यम है। कार्यालय की सीढ़ियां चढ़कर आने

वाला प्रत्येक सामान्य और गरीब व्यक्ति यहां से न्याय की आशा और संतोष के साथ लौटे, यह हमारी प्रार्थमिकता है। उन्होंने आगे कहा कि जनसंपर्क कार्यालय में प्राप्त होने वाले आवेदनों को प्रार्थमिकता देकर उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर भी निर्देश दिए गए हैं।

पहले नागरिकों को शिकायत या प्रस्तुति दर्ज कराने के लिए विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब इस सिंगल-विंडो जैसी पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से समय पर शिकायतों का निवारण संभव हो पाया है। आइए, जनसंपर्क केंद्र की संपूर्ण कार्यप्रणाली को समझते हैं :

**आवेदन स्वीकार करना और प्रारंभिक पंजीकरण**  
केंद्र पर आने वाले प्रत्येक नागरिक का विवरण रियेप्शन डेस्क पर दर्ज किया जाता है। उन्हें सुनवाई के लिए अनुकूल और तनावमुक्त वातावरण उपलब्ध कराया जाता है।

**अधिकारी द्वारा प्रत्यक्ष सुनवाई**  
उपस्थित वरिष्ठ एवं जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा आवेदक प्रस्तुतियों को ध्यानपूर्वक सुनकर मामले का विवरण दर्ज किया जाता है।

**पंजीकरण और त्वरित प्रक्रिया**  
केंद्र के माध्यम से प्राप्त सभी शिकायतों और प्रस्तुतियों का विधिवत पंजीकरण कर आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित जिला अथवा शहर पुलिस इकाइयों एवं संबद्ध शाखाओं को भेजा जाता है।

**रिपोर्ट तथा समीक्षा**  
फील्ड यूनिट के पास से निर्धारित समय में जरूरी रिपोर्ट मंगाकर उसका सूक्ष्म परीक्षण किया जाता है तथा आगे की कार्रवाई के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

**दो स्तरीय फीडबैक प्रणाली**  
सेवा सुधार के लिए कार्यालय एवं जिला स्तर; इन दो प्रकारों से विस्तृत फीडबैक फॉर्म भराया जाते हैं। टेलीफोन द्वारा संपर्क कर केस की प्रगति की जानकारी भी दी जाती है। गत 2 फरवरी से शुरू किए गए इस

जनसंपर्क कार्यालय में प्राप्त शिकायतों में से अधिकांश का त्वरित तथा सटीक निवारण किया गया है। भावनगर के श्री जिंगरभाई न्हुं ने गांधीनगर स्थित जनसंपर्क कार्यालय का संपर्क किया। कार्यालय के त्वरित फॉलोअप तथा पीआईएल पलक व पीएसआई एम. जे. पटेल के सहयोग से आवेदक की सम्बद्ध आईपीएस श्रीमती अमिता वनाणी से मुलाकात करवाकर उनके आवेदन को त्वरित गिरफ्तार किया गया और उनकी समस्या का निवारण किया गया। साणंद के आवेदक नरेशभाई दुलेरा ने इस सेवा को आम आदमी के लिए न्याय की आशा किरण तथा जनहित के लिए शुरू की गई उत्तम पहल बताया। जनसंपर्क कार्यालय केवल आवेदन स्वीकार करने का केन्द्र नहीं है, बल्कि पुलिस एवं जनता के बीच विश्वास का सुदृढ़ सेतु है। यह नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण पुलिस प्रशासन को अधिक लोकभोय, लोकोपयोगी और जिम्मेदार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

## वाल्मीकि समाज ने अखिल भारतीय सफाईकर्मी कांग्रेस के नेता छगनभाई सोलंकी को श्रद्धांजलि अर्पित की

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। छगनभाई सोलंकी ने वर्षों तक अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी कांग्रेस के नेता के रूप में कार्य किया। वे सन् 1960 से समाज के जरूरतमंद बच्चों को पाठ्यपुस्तकें और नोटबुक उपलब्ध कराते आ रहे थे। वडोदरा शहर के वाल्मीकि समुदाय के सामाजिक कार्यकर्ताओं जैसे अंबालाल मोतीलाल सोलंकी मोरखाला, दलपतसिंह सोलंकी गोत्री, मगनभाई देसाई वडोदरा, वडोदरा जिले के अनुभवी सामाजिक कार्यकर्ता सोमभाई कालिदास सोलंकी, रंशिकान्त शंकरलाल वैष्णव, मनीलाल सोलंकी और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने वडोदरा शहर और जिले के वाल्मीकि समुदाय के उत्थान और समाज के विकास के लिए सराहनीय कार्य किए,

लेकिन छगनभाई सोलंकी की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी। सन् 1950 से 1980 के बीच वे वडोदरा शहर में कई बड़े सम्मेलन और सभाएं आयोजित करते थे और सामाजिक जागरूकता के लिए प्रयास करते थे। उनके दृष्टिकोण पर गुजरात प्रदेश वाल्मीकि समाज और गुजरात प्रदेश नगर निगम कर्मचारी कांग्रेस के अध्यक्ष भाई लाल भी. वैष्णव ने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। ईश्वर उनकी आत्मा को शाश्वत शांति प्रदान करें। गुजरात प्रदेश वाल्मीकि समाज के महासचिव कतिभाई सोलंकी आदि ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की है कि वे उनके परिवार पर आई विपत्ति को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

## पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम: अब जैव-विघटित पाउच में मिलेगा मदर डेयरी का दूध

नई दिल्ली। बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण और पर्यावरणीय चुनौतियों के बीच देश की प्रमुख डेयरी कंपनी मदर डेयरी ने एक महत्वपूर्ण और दूरगामी पहल की घोषणा की है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून से कंपनी दिल्ली-एनपीआर क्षेत्र में अपने गाय के दूध की बिक्री ऐसे विशेष पाउच में शुरू करेगी, जो प्राकृतिक रूप से मिट्टी में विघटित हो सकेगी। इस कदम को देश के डेयरी क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल माना जा रहा है। पिछले कई वर्षों से प्लास्टिक कचरा दुनिया भर के देशों के लिए गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। दूध, खाद्य पदार्थों और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की पैकेजिंग में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, जो लंबे समय तक पर्यावरण में बना रहता है। इसके कारण मिट्टी, जल स्रोतों और पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसे समय में मदर डेयरी की यह पहल पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास के प्रयासों को नई दिशा देने वाली मानी जा रही है।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के अध्यक्ष मोनशा शाह ने इस नई तकनीक की जानकारी देते हुए बताया कि कंपनी द्वारा विकसित किए गए नए दूध पाउच इस प्रकार तैयार किए गए हैं कि वे कुछ वर्षों के भीतर प्राकृतिक रूप से मिट्टी में विघटित हो जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पर्यावरण-अनुकूल पहल का बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जाएगा और दूध की कीमतों में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जाएगी। इससे उपभोक्ताओं को बिना अतिरिक्त खर्च के पर्यावरण हितैषी उत्पाद प्राप्त होंगे।

विशेषज्ञों के अनुसार भारत में प्रतिदिन लाखों लीटर दूध की आपूर्ति प्लास्टिक पाउचों के माध्यम से की जाती है। उपयोग के बाद इनमें से बड़ी मात्रा में पाउच कचरे के रूप में पर्यावरण में पहुंच जाते हैं। यद्यपि पुनर्चक्रण की व्यवस्था मौजूद है, लेकिन वास्तविकता यह है कि बड़ी मात्रा में प्लास्टिक पुनर्चक्रण प्रक्रिया तक नहीं पहुंच पाता। ऐसे में जैव-विघटित पैकेजिंग का उपयोग भविष्य के लिए एक प्रभावी समाधान माना जा रहा है। मदर डेयरी द्वारा प्रस्तुत नई पैकेजिंग में विशेष प्रकार की उन्नत तकनीक का उपयोग किया गया है। कंपनी के अनुसार यह सामग्री समय के साथ प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से जैव-उपलब्ध मॉम में परिवर्तित हो जाती है। इसके बाद मिट्टी में मौजूद सूक्ष्मजीव इस पदार्थ को धीरे-धीरे विघटित कर पर्यावरण में मिला देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान प्लास्टिक के स्थायी और हानिकारक अवशेष नहीं बचते, जो पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मोनशा शाह ने कहा कि यह केवल एक नया उत्पाद नहीं है, बल्कि देश के डेयरी उद्योग में एक नई सोच का प्रतिनिधित्व करता है। उनके अनुसार भारत में पहली बार किसी बड़े स्तर पर दूध वितरण के लिए ऐसा पाउच उपयोग में लाया जा रहा है, जो प्राकृतिक रूप से नष्ट होने की क्षमता रखता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में अन्य डेयरी कंपनियों भी इस दिशा में कदम बढ़ाएंगी और पूरे उद्योग में पर्यावरण-अनुकूल पैकेजिंग को बढ़ावा मिलेगा। मदर डेयरी के प्रबंध निदेशक जयतीर्थ चारी ने बताया कि इस तकनीक को विकसित करने में चार वर्षों से अधिक समय तक

अनुसंधान और परीक्षण किया गया है। वैज्ञानिकों, तकनीकी विशेषज्ञों और पैकेजिंग इंजीनियरों की टीम ने यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार कार्य किया कि नई पैकेजिंग दूध की गुणवत्ता, सुरक्षा और भंडारण क्षमता पर किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव न डाले। कई चरणों के परीक्षण और गुणवत्ता मूल्यांकन के बाद इस तकनीक को व्यावसायिक उपयोग के लिए तैयार किया गया। उन्होंने बताया कि नया पाउच केवल जैव-विघटित ही नहीं है, बल्कि पुनर्चक्रण योग्य भी है। इससे दोहरा लाभ प्राप्त होगा। एक ओर यदि पाउच पुनर्चक्रण प्रणाली तक पहुंचता है तो उसका पुनः उपयोग किया जा सकता, वहीं यदि वह पर्यावरण में पहुंच भी जाए तो लंबे समय तक प्रदूषण का कारण नहीं बनेगा। यह विशेषता इसे पारंपरिक प्लास्टिक पैकेजिंग से अलग बनाती है। पर्यावरण विशेषज्ञों ने मदर डेयरी की इस पहल का स्वागत किया है। उनका मानना है कि भारत जैसे विशाल उपभोक्ता बाजार में यदि बड़े पैमाने पर जैव-विघटित पैकेजिंग का उपयोग शुरू होता है तो इसका सकारात्मक प्रभाव राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई देगा। इससे प्लास्टिक कचरे की मात्रा में कमी आएगी और नगर निकायों पर कचरा प्रबंधन का दबाव भी कम होगा। देश में हर वर्ष लाखों टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है। केंद्र और राज्य सरकारों लगातार एकल-उपयोग प्लास्टिक को कम करने तथा टिकाऊ विकल्पों को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य कर रही हैं। ऐसे में निजी क्षेत्र की कंपनियों की भागीदारी इस अभियान को और प्रभावी बना सकती है।

## गुजरात तट पर मादक पदार्थों की तस्करी में वृद्धि: सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक गंभीर चुनौती

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। गुजरात के सामने सबसे बड़ी चुनौती इसकी विशाल तटरेखा है। इसका प्रसार तेजी से हो रहा है। यह खतरा बड़े शहरों से लेकर दूरदराज के गांवों तक फैल चुका है। भूमि और समुद्री मार्गों से अन्य देशों से मादक पदार्थों की बड़े पैमाने पर तस्करी जारी है। हाल ही में, तटरक्षक बल और गुजरात आतंकवाद-विरोधी दस्ते (एटीएस) ने एक संयुक्त अभियान में कच्छ के मुंद्रा तट के पास एक जहाज से लगभग 1150 करोड़ रुपये मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए। सवाल यह है कि

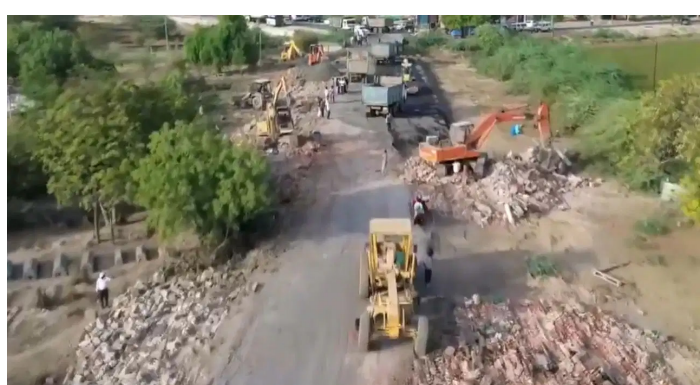
गुजरात अधिकाधिक मादक पदार्थों का पारगमन केंद्र क्यों बनता जा रहा है? पिछले कुछ वर्षों से राज्य में सुरक्षा बल इस तरह की अवैध गतिविधियों से निपटने के लिए लगातार अभियान चला रहे हैं। इन तमाम प्रयासों के बावजूद अगर समुद्री मार्गों से होने वाली मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम नहीं लग पा रही है, तो इसके मूल कारण क्या हो सकते हैं? आखिर सुरक्षा एजेंसियां समुद्री मार्गों से इतनी बड़ी मात्रा में मादक पदार्थों की तस्करी करती हैं और उन्हें देश के विभिन्न हिस्सों में वितरित करने वाले मुख्य

अपराधियों को पकड़ने में असमर्थ क्यों हैं? क्योंकि पिछले पांच वर्षों से गुजरात के तटीय इलाकों में लगातार हो रही ड्रग्स की बरामदगी से यह स्पष्ट होता है कि यहाँ ड्रग्स की तस्करी लगातार जारी है। जब तक इन ड्रग माफिया नेटवर्क को जड़ से खत्म नहीं किया जाता, तब तक ये मौत के सौदागर ड्रग्स के जहर से हमारे देश को तबाह करते रहेंगे। देश का विकास जारी रहेगा, लेकिन देश को विनाश की ओर ले जा रहे इन दुष्ट तत्वों की पहचान करना और उन्हें तुरंत खत्म करना बेहद जरूरी है।

## अहमदाबाद में सड़क विकास के लिए बड़ा अभियान, अतिक्रमण हटाकर खाली कराई 4,000 वर्ग मीटर सरकारी भूमि

### स्टेट हाईवे-17 के चौड़ीकरण का रास्ता साफ, प्रशासन ने दरगाहों, दुकानों और कब्रिस्तान के हिस्से पर की कार्रवाई; भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अभियान शांतिपूर्वक संपन्न

अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद जिले में सड़क अवसंरचना को मजबूत बनाने और क्षेत्रीय संपर्क व्यवस्था को बेहतर करने की दिशा में जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए स्टेट हाईवे-17 के चौड़ीकरण के लिए बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। प्रशासन द्वारा संचालित इस अभियान के दौरान सरकारी भूमि पर बने विभिन्न निर्माणों को हटाया गया, जिनमें धार्मिक और व्यावसायिक संरचनाएं भी शामिल थीं। अधिकारियों के अनुसार कार्रवाई का उद्देश्य केवल सड़क विस्तार परियोजना के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराना था, ताकि लंबे समय से प्रस्तावित विकास कार्यों को गति दी जा सके।



इसी परियोजना के अंतर्गत सोमवार को अहमदाबाद जिले के विरामगाम क्षेत्र में व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अधिकारियों के अनुसार जिन संरचनाओं को हटाया गया उनमें तीन दरवाहें, छह दुकानें तथा एक कब्रिस्तान का सीमित हिस्सा शामिल था। प्रशासन का कहना है कि सभी निर्माण सरकारी भूमि पर सड़क परियोजना की निर्धारित सीमा के भीतर आ रहे थे और परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए इन्हें हटाना आवश्यक था। अभियान की संवेदनशीलता को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने पहले से ही व्यापक तैयारियां की थीं। अधिकारियों ने बताया कि पिछले दो महीनों से इस कार्रवाई की योजना बनाई जा रही थी और संबंधित सभी पक्षों के साथ आधुनिकीकरण का निर्णय लिया था।

अहमदाबाद ग्रामीण क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों के अनुसार अभियान को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न करने के लिए स्टेट हाईवे-17 के लगभग सड़क विस्तार कार्य प्रभावित हो रहा था। प्रशासन और पुलिस विभाग ने इन दोनों क्षेत्रों में सुरक्षा घेरा बनाकर कार्रवाई की गई ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना या कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो।

अधिकारियों के मुताबिक कब्रिस्तान का केवल वही हिस्सा हटाया गया जो सड़क चौड़ीकरण परियोजना की सीमा में आ रहा था। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि लगभग छह मीटर भूमि परियोजना के लिए आवश्यक थी और इसी कारण सीमित क्षेत्र में कार्रवाई की गई। इस दौरान स्थानीय प्रतिनिधियों और समुदाय के जिम्मेदार लोगों को भी पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी गई। पुलिस और प्रशासन का कहना है कि अभियान के दौरान कहीं से किसी बड़े विरोध, तनाव या हिंसक प्रतिक्रिया के संकेत नहीं मिले। पूरी कार्रवाई कानून के दायरे में और पूर्ण निष्पत्ति योजना के अनुसार संपन्न की गई। अधिकारियों ने इसे प्रशासन और स्थानीय समुदायों के बीच संवाद और सहयोग का सकारात्मक उदाहरण बताया। गंगासर झील के आपास का क्षेत्र इस कार्रवाई का प्रमुख केंद्र रहा। अधिकारियों के अनुसार स्टेट हाईवे-17 के लगभग 400 मीटर लंबे हिस्से पर विभिन्न प्रकार के अतिक्रमण मौजूद थे, जिसके कारण सड़क विस्तार कार्य प्रभावित हो रहा था। अभियान के बाद करीब 4,000 वर्ग मीटर सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। अब इस भूमि का उपयोग सड़क चौड़ीकरण और अन्य अवसंरचनात्मक कार्यों के लिए किया जाएगा।

परियोजना से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण पूरा होने के बाद क्षेत्र में यातायात व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा। वर्तमान में यह मार्ग कई स्थानों पर संकरा होने के कारण दुर्घटनाओं और यातायात जाम की समस्या का सामना करता है। सड़क के विस्तारित होने से न केवल यात्रा समय कम होगा बल्कि भारी वाहनों और माल परिवहन को भी सुविधा मिलेगी। राज्य सरकार का मानना है कि बेहतर सड़क नेटवर्क क्षेत्रीय विकास का आधार बनता है। अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर और राजकोट जैसे महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ने वाले इस मार्ग के उन्नयन से व्यापार, उद्योग, कृषि परिवहन और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय व्यवसायों और परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी इससे दीर्घकालिक लाभ मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा पिछले वर्ष इस सड़क परियोजना का शुभारंभ किया गया था और तब से इसके विभिन्न चरणों का पता चल रहा है। सड़क के आधुनिकीकरण के तहत चौड़ीकरण, बेहतर जल निकासी व्यवस्था, सुरक्षा सुविधाएं और यातायात प्रबंधन से जुड़े कार्यों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए किया जाएगा।

## सूरत में भीषण बस हादसा: टक्कर के बाद आग का तांडव, कई यात्री जिंदा जले; 7 की मौत, दर्जनों घायल

सूरत। गुजरात के सूरत जिले में मंगलवार को हुए एक भयावह सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। बारडोली के निकट धुलिया राजमार्ग पर दो यात्री बसों की आमने-सामने हुई भीषण टक्कर का कारण बस में आग लग गई, जिससे कई यात्रियों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। हादसे में कम से कम सात लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि अनेक यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। प्रशासन को आशंका है कि घायलों में कुछ की हालत अत्यंत गंभीर होने के कारण मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। यह दुर्घटना बारडोली तालुका के उवा और मांकरपुर गांवों के बीच उस समय हुई, जब गुजरात राज्य परिवहन निगम की एक बस और महाराष्ट्र राज्य परिवहन की एक बस आमने-सामने टकरा गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जोरदार थी कि गुजरात परिवहन निगम की बस संतुलन

खोकर सड़क पर पलट गई। दुर्घटना के कुछ ही क्षण बाद बस से धुआं निकलना शुरू हुआ और देखते ही देखते उसमें आग भड़क उठी। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि आग लगने से पहले एक तेज धमाका जैसी आवाज भी सुनाई दी, जिसके बाद बस के भीतर बैठे यात्रियों में अफ़स-तफ़री मच गई। कुछ यात्री खिड़कियों और आपातकालीन निकास के रास्ते बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन कई लोग बस के अंदर ही फंस गए। आग इतनी तेजी से फैली कि उन्हें बाहर निकलने का अवसर नहीं मिला पाया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतकों में कुछ ऐसे यात्री भी शामिल हैं जो आग की लपटों में घिरकर जिंदा जल गए। अधिकारियों के मुताबिक महाराष्ट्र राज्य परिवहन की बस धुलिया से नवापुर होते हुए सूरत की ओर जा रही थी। इसी दौरान सामने से आ रही दूसरी बस के साथ उसकी



टक्कर हो गई। दुर्घटना के वास्तविक कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है, जिनमें वाहन की गति, सड़क की स्थिति, चालक की प्रतिक्रिया और तकनीकी कारण शामिल हैं। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने राहत

कार्य शुरू कर दिया और बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने का प्रयास किया। कुछ ही देर में पुलिस, प्रशासन और अग्निशमन विभाग की टीमें भी घटनास्थल पर पहुंच गईं। बारडोली फायर ब्रिगेड के जवानों ने आग बुझाने के लिए कई दमकल वाहनों की मदद ली। काफी मशकत

के बाद आग पर नियंत्रण पाया जा सका, लेकिन तब तक भारी नुकसान हो चुका था। राहत और बचाव दलों ने घायल यात्रियों को तत्काल नजदीकी अस्पतालों में पहुंचाया। कई घायलों को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। चिकित्सकों का कहना है कि कुछ मरीजों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। प्रशासन ने अस्पतालों को अलर्ट पर रखा है और ज़रूरत पड़ने पर अतिरिक्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। दुर्घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों ने राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की और घायलों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और उनकी पहचान की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि लंबी दूरी की यात्री बसों में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। दुर्घटना के बाद आग लगने की घटनाएं अक्सर अधिक जानलेवा साबित होती हैं क्योंकि यात्रियों को बाहर निकलने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। ऐसे मामलों में आपातकालीन निकास, अग्निशमन उपकरण और नियमित तकनीकी जांच की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। हादसे की खबर सामने आते ही पूरे देश में शोक की लहर फैल गई। प्रधानमंत्री Narendra Modi ने भी इस दुर्घटना पर गहरा दुःख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी संदेश में कहा गया कि सूरत जिले में हुई दुर्घटना अत्यंत दुःखद है और जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं। साथ ही घायलों

के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की गई। संदेश में यह भी कहा गया कि स्थानीय प्रशासन और राहत एजेंसियां घटनास्थल पर हर संभव सहायता उपलब्ध कराने में जुटी हुई हैं। राज्य सरकार ने भी दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की जाएगी और यदि किसी प्रकार की लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग भी दोनों बसों की तकनीकी स्थिति और परिचालन रिकॉर्ड की जांच करेगा। स्थानीय लोगों के अनुसार दुर्घटना का दृश्य अत्यंत भयावह था। सड़क पर पलटी बस, अत्यंत उड़ती आग की ऊंची लपटें और मदद के लिए पुकारते यात्री लंबे समय तक लोगों के मन में बने रहेंगे। कई प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने

यात्रियों को बस से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन आग की तीव्रता के कारण सभी तक पहुंच पाना संभव नहीं हो सका। सूरत और आपास के क्षेत्रों में इस हादसे के बाद शोक का माहौल है। प्रशासन ने मृतकों के परिवारों के लिए जीवनभर का दर्द बन गई है। जिन लोगों ने अपने परिवारों को खोया है, उनके लिए यह क्षति अपूरणीय है। अब सभी की निगाहें सड़क रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आखिर इतनी भयावह दुर्घटना कैसे हुई और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए।